एप्पेलेट सिविल

D. K. Mahajan and B. S. Dhillon, न्यायमूर्ति. के समक्ष,

जसवांट ई. टी. सी.-अपीलार्थी।

बनाम।

श्रीमती बसंती देवी,-प्रतिवादी।

.A.O. नं. 1968 का 86.

20 अप्रैल, 1970।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXIX)-धारा 22-क्या अचल संपत्ति-कृषि भूमि के पूर्ण हस्तांतरण पर लागू होता है-चाहे वह धारा द्वारा कवर किया गया हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्ण अंतरण भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उपधारा (1) के दायरे में आता है। खंड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखने वाले शब्दों में इस प्रकार एक पूर्ण स्थानांतरण शामिल है, अन्यथा यह खंड अप्रासंगिक हो जाएगा और इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यद्यपि यह धारा बहुत ही असंतुष्ट रूप से लिखी गई है, फिर भी इस खंड में ही विधानमंडल के इरादे का संकेत है। अधिनियम के लागू होने के बाद अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों में आने वाले अजनबियों को बाहर रखने के लिए प्रावधान लागू किया गया है। न्यायालयों को विधायी प्रावधान को तब तक अर्थ देना चाहिए जब तक कि न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है कि यह वास्तव में विधायी होगा और इसकी व्याख्या नहीं करेगा।

अभिनिर्धारित है कि धारा 22 कृषि भूमि के हस्तांतरण का उपबंध नहीं करती है। यह केवल एक प्रकार का पूर्व-मुक्ति का अधिकार देता है। प्रविष्टि नं. भारत के संविधान, 1950 की अनुसूची VII की सूची III में 6 स्पष्ट रूप से कृषि भूमि को समवर्ती सूची के दायरे से बाहर करता है। कृषि भूमि को विशेष रूप से प्रविष्टि सं. संविधान की सूची 2 का 18, एकमात्र अपवाद हस्तांतरण के मामले में है। इसलिए, अधिनियम की धारा 22 में कृषि भूमि शामिल नहीं है।

माननीय न्यायमूर्ति डी. के. महाजन द्वारा 21 फरवरी, 1969 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजा गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. महाजन और माननीय न्यायमूर्ति श्री भूपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ ने अंततः 20 अप्रैल, 1970 को मामले का फैसला सुनाया।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव, दिनांक 11 जून, 1968 के न्यायालय के आदेश से दूसरी अपील, जिसमें श्री इंदर मोहन मलिक, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी, जिला गुड़गांव, दिनांक 16 मार्च, 1968 के आदेश को उलट दिया गया था (लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना दोनों वादियों के वाद को खारिज करते हुए) और गुणदोष पर निर्णय के लिए मामले को निम्न न्यायालय को भेज दिया गया था और पक्षकारों को 24 जून, 1968 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

डिवीजन बेंच का निर्णयः

न्यायमूर्ति महाजन ने न्यायालय का निर्णय सुनाया।

(1) 21 फरवरी 1969 के मेरे आदेश के अनुसरण में, मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था और इस तरह इसे हमारे सामने रखा गया है।

(2) इस मामले के तथ्य संदर्भ क्रम में दिए गए हैं और मैं उसी क्रम से पुनः प्रस्तुत कर रहा हूंः —

उन्होंने कहा, "तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। रंजीत विवादित संपत्ति के अंतिम पुरुष धारक थे। उनकी मृत्यु पर "हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद, उनकी दो बेटियाँ मूर्ति देवी और बसंती देवी उनकी उत्तराधिकारी बनीं। मूर्ति देवी ने विवाद में संपत्ति बेच दी और बसंती देवी द्वारा बिक्री को पूर्व-खाली करने की मांग की गई। मुकदमे में, प्रतिशोधियों की याचिका पर एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया गया था कि बसंती देवी की शिकायत में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था। इस तर्क का आधार यह था कि पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट की धारा 15 (2) के तहत, जैसा कि 1960 के पंजाब प्री-एम्पशन (संशोधन) एक्ट X द्वारा संशोधित किया गया था, प्री-एम्प्टर मूर्ति

देवी की एक बहन को प्री-एम्पशन का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, बसंती देवी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर निर्भरता रखी जो नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः -

(1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, किसी निर्वसीयत की किसी स्थावर संपत्ति या उसके द्वारा किए गए किसी कारबार में, चाहे वह केवल या दूसरों के साथ मिलकर हो, ब्याज अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों को सौंपा जाता है और ऐसे उत्तराधिकारियों में से कोई एक संपत्ति या व्यवसाय में अपने हित को अंतरित करने का प्रस्ताव करता है, वहां अन्य उत्तराधिकारियों को अंतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित ब्याज प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार होगा।

(2) वह प्रतिफल जिसके लिए इस धारा के अधीन मृतक की संपत्ति में कोई हित अंतरण किया जा सकता है, पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अभाव में, इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यदि ब्याज अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्धारित प्रतिफल के लिए इसे अर्जित करने को इच्छुक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आवेदन की सभी लागतों या घटना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन ब्याज अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाले अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट दो या अधिक उत्तराधिकारी हैं, तो उस उत्तराधिकारी को वरीयता दी जाएगी जो अंतरण के लिए उच्चतम प्रतिफल प्रदान करता है।

"निचली अदालत ने बसंती देवी के इस तर्क को नकार दिया कि धारा 22 लागू होगी। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण यह थे कि धारा 22 केवल वहां लागू होती है जहां संपत्ति के अंतरण का प्रस्ताव होता है न कि जहां संपत्ति का पूर्ण अंतरण होता है। बसंती देवी की अपील पर, निचली अपीलीय अदालत ने यह विचार लिया है कि धारा 22 लागू होती है और निचली अपीलीय अदालत के साथ जो कारण प्रचलित है वह यह है कि धारा 22 वास्तव में पूर्व-मुक्ति का अधिकार प्रदान करती है। यह भी कहा गया है कि प्री-एम्पशन के इस नियम को पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में वर्तमान दूसरी अपील दायर की गई है।"

(4) यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 की व्याख्या है जिससे हम इस मामले में संबंधित हैं। दो प्रश्न उठते हैंः (1) क्या यह उपबंध पूर्ण अंतरणों पर लागू होता है; और (2) क्या यह कृषि भूमि पर लागू होता है। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, कम से कम कहने के लिए, यह खंड बहुत दुखी शब्दों में लिखा गया है। हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि इस धारा में ही विधानमंडल के इरादे का संकेत है। यह प्रावधान अधिनियम के लागू होने के बाद अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों में आने वाले अजनबियों को बाहर रखने के लिए अधिनियमित किया गया है।

अपीलार्थी-विक्रेताओं के विद्वान वकील श्री जे. वी. गुप्ता का तर्क है कि धारा 22 के संदर्भ में लागू नहीं होती है क्योंकि यह केवल संपत्ति के प्रस्तावित हस्तांतरण के मामले को शामिल करती है न कि उन मामलों को जहां संपत्ति वास्तव में हस्तांतरित की गई है। मुख्य रूप से उपधारा (1) में "अंतरण का प्रस्ताव" वाक्यांश पर निर्भरता रखी गई है और धारा 22 की उपधारा (2) पर फिर से बल दिया गया है, जिसमें पुनः प्रयोग किया गया अपवाद "इस धारा के अधीन अंतरण किया जा सकता है" और साथ ही "यदि ब्याज अर्जित करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति इसे प्राप्त करने को इच्छुक नहीं है" पद के आगे उपयोग के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह की भाषा का उपयोग उप-धारा में किया गया है (3).

(5) यदि इस धारा की शाब्दिक व्याख्या की जाती है, तो ये कठिनाइयाँ सामने आती हैं, लेकिन तब यह प्रावधान अनुचित हो जाएगा और इसे स्थानांतरित करने का निर्णय ज्ञात होने से पहले ही एक गुप्त हस्तांतरण या खुले हस्तांतरण द्वारा इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। मेरी राय में, स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित शब्दों में एक पूर्ण स्थानांतरण शामिल है। एक बार इस व्याख्या को रखे जाने के बाद, धारा 22 काम करेगी और प्रभावी हो जाएगी। जब अपीलार्थियों के विद्वत वकील को यह बताया गया, तो उन्होंने तर्क दिया कि धारा 22 की उप-धारा (2) अनुचित हो जाएगी क्योंकि पूर्ण अंतरण के मामले में, न्यायालय के कदम उठाने और कीमत तय करने का कोई सवाल ही

नहीं होगा यदि कोई ईमानदार और वैध अनुबंध है। ऐसा नहीं होगा। यदि उचित बाजार मूल्य का भुगतान किया गया है तो मूल्य निर्धारित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। किसी भी मामले में, उप-धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सह-उत्तराधिकारी को निर्धारित मूल्य स्वीकार करने से रोकता हो। लेकिन यदि निर्धारित कीमत काल्पनिक है, तो अदालतें उप-धारा के तहत कीमत निर्धारित करेंगी। अन्य प्रकार के हस्तांतरण हैं जैसे उपहार और आदान-प्रदान। इस प्रकार के स्थानान्तरणों में, पूर्ण होने पर भी, उप-धारा लागू होगी। इसलिए, यह सुझाव देना बेकार है कि प्रत्येक मामले में उपधारा (2) कठिनाई पेश करेगी जब इसे पूर्ण हस्तांतरण पर लागू करने की मांग की जा रही है।

(6) मेरी राय में, धारा की व्याख्या करने और उसका अर्थ देने का सही तरीका यह मानना है कि एक पूर्ण अंतरण भी उपधारा (1) के दायरे में आता है और इस प्रकार अंतरण के लिए प्रस्तावित शब्दों में एक पूर्ण अंतरण भी शामिल होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अन्यथा यह खंड पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाएगा। यह निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत है कि न्यायालयों को एक विधायी प्रावधान को तब तक अर्थ देना चाहिए जब तक कि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर मजबूर नहीं किया जाता है कि यह वास्तव में विधायी होगा और इसकी व्याख्या नहीं करेगा।

(7) प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रश्न में कठिनाई का पता चलता है जो सूची ॥ में प्रविष्टि संख्या 18 और प्रविष्टि संख्या में विज्ञापन देना है। 7वीं अनुसूची की सूची ॥॥ में 5 और 6। संदर्भ की सुविधा के लिए, उन प्रविष्टियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

सूची ॥-प्रविष्टि सं। 18. भूमि, अर्थात्, भूमि में या उस पर अधिकार, भूस्वामी और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल और किराए का संग्रह; कृषि भूमि सुधार और कृषि ऋणों का हस्तांतरण और अलगाव; उपनिवेशीकरण।

सूची ॥॥-प्रविष्टि संख्या. 5...Marry और तलाक; शिशुओं और नाबालिगों; गोद लेने; वसीयत; निर्विकारता और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन; सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से पहले अपने व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।

प्रविष्टि नं. 6... कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।

(8) यह उत्तराधिकार के मामले में कृषि भूमि पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के प्रश्न से निपटने का अवसर था और मैंने प्रविष्टि सं. भारत के संविधान की सूची 2 का 18, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में इसके विपरीत भाग के साथ, अर्थात् प्रविष्टि सं. 21. मैंने बताया कि इन दोनों प्रविष्टियों की भाषा में भौतिक अंतर थे क्योंकि उक्त प्रविष्टि से हस्तांतरण निकाला गया था और समवर्ती प्रविष्टि नं। सूची ॥॥ का 5 जिसने केंद्रीय संसद को उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाया। लेकिन कृषि भूमि के मामले में ऐसा नहीं है। प्रविष्टि नं. सूची 3 का 6, जब पढ़ा जाता है, यह इंगित करता है कि केंद्रीय संसद को प्रविष्टि संख्या 3 के तहत अपनी शक्ति से परे कृषि भूमि पर कानूनी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं है। सूची ॥॥ का 5, अर्थात् हस्तांतरण के संबंध में है। अतः यह स्पष्ट है कि धारा 22 कृषि भूमि के मामले को शामिल नहीं करेगी।

(9) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री रूप चंद ने जोर देकर कहा कि धारा 32 में उपयोग किए गए अचल संपत्ति शब्दों में कृषि भूमि शामिल होगी। निस्संदेह, वे करते हैं। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब केंद्रीय विधानमंडल ने इन शब्दों का उपयोग किया था तो उसने पूरी तरह से जानते हुए ऐसा किया था कि उसके पास हस्तांतरण के उद्देश्यों को छोड़कर कृषि भूमि के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। धारा 22 में कृषि भूमि के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। यह केवल एक प्रकार का पूर्व-मुक्ति का अधिकार देता है। वास्तव में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, प्रविष्टि सं। सूची ॥॥ में 6 स्पष्ट रूप से कृषि भूमि को समवर्ती सूची के दायरे से बाहर निकालता है। कृषि भूमि को विशेष रूप से प्रविष्टि सं. सूची ॥ का 18. एकमात्र अपवाद हस्तांतरण के मामले में है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 22 में कृषि भूमि शामिल नहीं है।

(10) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री रूप चंद का अंतिम तर्क था कि धारा 22 अधिकार से बाहर है क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल को कृषि भूमि के संबंध में ऐसा कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि विधानमंडल उन मामलों के संबंध में कानून पारित कर रहा था जिन्हें पारित करने की उसकी कोई शक्ति नहीं थी, विशेष रूप से जब कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्ति के संबंध में, उसके पास ऐसा कानून बनाने की शक्ति है। इस दृष्टिकोण को हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, (1) में संघीय न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है, जिसमें इसी तरह की स्थिति में संघीय न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने सटीक तर्कों पर हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के प्रावधानों को निरस्त करने से इनकार कर दिया था।

(11) ऊपर अभिलिखित कारणों के लिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, विद्वत निचली अपीलीय अदालत के निर्णय और डिक्री को दरकिनार करते हैं और विद्वत निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से अलग आधारों पर बहाल करते हैं। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा)**